पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2414/2020

==========

सुरेश कुमार चौबे, पिता-स्वर्गीय राजेंद्र चौबे, निवासी-मुहल्ला-प्रभुनाथ नगर, सदहा, थाना-छपरा मुफस्सिल, जिला-सारण छपरा।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अध्यक्ष, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक।

2. महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर।

3. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, छपरा।

4. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, छपरा।

... ... प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री राम बिनोद सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री प्रभाकर झा, अधिवक्ता

==========

रद्द करना - प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट या पत्र संख्या एचओ/डीएडी/11/18-19 संख्या 383 दिनांक 20/12/2018 में निहित आरोप के ज्ञापन को रद्द करने के लिए कोई अन्य उपयुक्त रिट, जिसके तहत अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट आरोपों पर ऋण की मंजूरी की तारीख से 11 साल की समाप्ति के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और पत्र संख्या में निहित जांच प्राधिकारी / जांच रिपोर्ट दिनांक 13/6/2019 के निष्कर्ष को रद्द करने के लिए कोई उपयुक्त रिट। एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या-135 दिनांक 29/5/2019 जिसके द्वारा गलती से जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोप संख्या 1 साबित पाया गया है - जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी पत्र संख्या एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या 186 दिनांक 1/8/2019 में निहित आदेश को रद्द करने और अन्य को रद्द करने के लिए - याचिकाकर्ता को 2004-2010 से स्केल 1 में

क्षेत्रीय कार्यालय, छपरा के तहत झौवां शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात किया गया था - उक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने न्यायसंगत बंधक के तहत उधारकर्ताओं की अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के बाद कुछ ऋण स्वीकृत किए - इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में उधारकर्ताओं से कुछ एलआईसी बांड भी प्राप्त किए - याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2010 में स्केल - II में पदोन्नत किया गया और उन्हें सिवास में मलमलिया शाखा में और फिर छपरा में क्षेत्रीय कार्यालय के तहत पकारी शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया सुरक्षा के रूप में लिए गए 43 बांडों में से 10 बांड नकली/जाली पाए गए और शेष 36 पॉलिसी बांड बैंक के पक्ष में नहीं सौंपे गए, जिसके कारण याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। 73,85,267/- प्लस ब्याज प्रतिवादी बैंक को – याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया – जांच अधिकारी ने 13/5/2019 को अपनी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की और बचाव पक्ष के प्रतिनिधि ने 28/5/2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें संख्या एचओ/डीएडी/12/19-20/संख्या 135 दिनांक 29/5/2019 है – याचिकाकर्ता ने 26/6/2019 को दूसरे कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया और 14/7/2019 को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए – याचिकाकर्ता ने 30/7/2019 को दूसरे कारण बताओ नोटिस के जवाब के समर्थन में एक याचिका भी दायर की लेकिन इन सभी को नजरअंदाज करते हुए अनुशासन समिति ने 'बर्खास्तगी' की सजा दी है जो सामान्य रूप से भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी, जैसा कि पत्र संख्या 187 दिनांक 1/8/2019 में निहित है - याचिकाकर्ता ने अध्यक्ष-सह-अपीलीय प्राधिकार, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के समक्ष 6/9/2019 को अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया लेकिन अपीलीय प्राधिकार ने अपील के आधार पर विचार किए बिना यांत्रिक तरीके से अनुशासनात्मक प्राधिकार द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 1/8/2019 को दी गई सजा को बरकरार रखा है। - ऋण स्वीकृत होने की तिथि से 11 वर्ष बीत जाने के बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई - विभागीय जांच कर्मचारी जवाबदेही नीति के खंड 7(xii) का घोर उल्लंघन है - इसके अनुसार किसी भी चूक के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, जिसे दो क्रमिक ऑडिट रिपोर्टों में या घटना की तारीख से चार साल, जो भी बाद में हो, में इंगित नहीं किया गया है। - दस्तावेजों के अवलोकन से इस न्यायालय को पता चला कि याचिकाकर्ता ने 2006-08 की अवधि के दौरान कुछ ऋण स्वीकृत किए हैं। - 20/12/2018 को चार्ज मेमो जारी किया गया और याचिकाकर्ता 31/12/2018 को सेवानिवृत्त हो 11 वर्ष - उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की उक्त नीति कि यह नीति दिनांक 11.01.2014 से लागू हुई। 12/3/2014 और 2018-19 में आरोप तय किए गए - आरोप तय होने के समय, उक्त स्टाफ जवाबदेही नीति अस्तित्व में आई और ग्रामीण बैंक के

कर्मचारियों और स्टाफ पर लागू थी - याचिकाकर्ता का मामला सबसे खराब स्थिति में लापरवाही के दायरे में आता है और निश्चित रूप से न तो धोखाधड़ी, न ही आपराधिक अपराध और न ही दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के तहत आता है - इसलिए अकेले इस आधार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की स्टाफ जवाबदेही नीति का खंड 7 (xii) याचिकाकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है - इसके अलावा यह भी इस अदालत के लिए है कि याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में विशेष रूप से दलील दी है कि ऋण उधारकर्ता की अचल संपत्ति प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किए गए थे- याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में उधारकर्ता से एलआईसी बांड भी प्राप्त किए थे - बैंक के अधिकारी इस मामले को दबाए बैठे रहे और अपनी खाल बचाने के लिए याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बना दिया जो सेवानिवृत्त होने वाला था आरोपों को खारिज किया जाता है – प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को उसकी सेवानिवृत्ति बकाया राशि से संबंधित भुगतान इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने के भीतर करे – रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान

मौखिक निर्णय

दिनांक: 01-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंध्याचल सिंह को सुना गया, जिनकी सहायता श्री राम बिनोद सिंह, विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने की- उत्तर ग्रामीण बैंक.

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के लिए दायर की गई है:-

> *i) पत्र संख्या एचओ/डीएडी/ में निहित आरोप ज्ञापन को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए पत्रांक एचओ/डीएडी/11/18-19 No.-383 दिनांक 20.12.2018 जिसके तहत ऋण स्वीकृत होने की तिथि से लगभग 11*

वर्ष बीत जाने के बाद अस्पष्ट एवं अनिर्दिष्ट आरोप के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।

ii) जारी करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट या जांच अधिकारी के निष्कर्ष/जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 को पत्र संख्या में निहित किसी अन्य उपयुक्त रिट को रद्द करने के लिए पत्रांक एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या-135 दिनांक 29.05.2019, जिसके द्वारा जांच अधिकारी गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 1 सिद्ध पाया गया है।

iii) रिट जारी करने के लिए पत्र संख्या में निहित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में पत्रांक एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या-186 दिनांक 01.08.2019 अनुशासनात्मक प्राधिकरण के हस्ताक्षर से जारी किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को "बर्खास्तगी" की समेकित सजा दी गई है, जो सामान्यतः विनियमन के अनुसार भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता होगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के धारा 39(1) (बी) (v) को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 के साथ पढ़ें।" (इसके बाद केवल "विनियम" के रूप में संदर्भित)।

iv) पत्र क्रमांक में निहित प्रशासनिक आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए। महाप्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (इसके बाद केवल "बैंक" के रूप में संदर्भित), मुजफ्फरपुर द्वारा पारित पत्रांक एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या-187 दिनांक 01.08.2019, जिसके तहत याचिकाकर्ता को " उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 के विनियम 39(I) (बी) (वी) के साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013." के अनुसार बर्खास्तगी सामान्यतः भावी रोजगार के लिए अयोग्यता मानी जाएगी।

v) पत्र संख्या एचओ/डीएडी/12/19-20 संख्या-322 दिनांक 23.10.2019 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण या किसी अन्य उपयुक्त रिट की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए अध्यक्ष-सह-अपीलीय प्राधिकरण, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर,जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ दायर अपील को बैंक के अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

vi) इस प्रकार की रिट जारी करने के लिए प्रतिवादियों को सेवानिवृत्ति बकाया सहित सभी परिणामी लाभ का भुगतान करने के लिए आवश्यक निर्देश देने के लिए परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, क्योंकि याचिकाकर्ता 31.12.2018 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।

vii) कोई अन्य उचित रिट या निर्देश जारी करने के लिए जिसे आपके माननीय न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और उचित समझें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता झाउवान शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात था। क्षेत्रीय कार्यालय, छपरा में स्केल-1 में 2004-2010 तक। उक्त अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने उधारकर्ताओं की कुछ अचल संपत्तियों को न्यायसंगत बंधक के तहत प्राप्त करने के बाद कुछ ऋण स्वीकृत किए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने कुछ एलआईसी बॉन्ड भी प्राप्त किए थे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के रूप में उधारकर्ताओं के लिए। याचिकाकर्ता को वर्ष 2010 में स्केल-II में पदोन्नत किया गया था और उसे सीवान जिले में मलमलिया शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय छपरा के तहत पुछरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि ऋण वितरण के उनके कार्य के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया था तथा उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर स्केल-II में पदोन्नति प्रदान की गई थी। लेकिन अपने करियर के अंतिम चरण

में, जब वे 31.12.2018 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, तो 20.12.2018 को उन्हें एक आरोप ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने संबंधित एलआईसी कार्यालय में पॉलिसी बांड की वास्तविकता का पता लगाए बिना और बिना आकलन किए जमानत के रूप में लिए गए एलआईसी पॉलिसी बांड पर विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए। आरोप लगाया गया कि सुरक्षा के रूप में लिए गए 43 बांडों में से सात (7) एलआईसी बांड नकली/जाली पाए गए और शेष 36 पॉलिसी बांड बैंक के पक्ष में आवंटित नहीं किए गए, जिसके कारण याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ। 73,85, 267/- के साथ ब्याज प्रतिवादी बैंक को दिया। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विभागीय कार्यवाही के दौरान, प्रबंधन प्रतिनिधि ने 13.05.2019 को जांच अधिकारी के समक्ष अपना लिखित बयान दाखिल किया (अनुलग्नक-5) और बचाव पक्ष के प्रतिनिधि ने 28.05.2019 को अपनी लिखित रिपोर्ट पेश की (अनुलग्नक-6)। जांच अधिकारी ने 13.06.2019 को अपनी लिखित रिपोर्ट पेश की, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट पेश करने से पहले ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने पत्र संख्या के तहत 29.05.2019 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। एचओ/डीएडी/12/19-20/सं. 135 दिनांक 29.05.2019 (अनुलग्नक-7)। याचिकाकर्ता ने 26.06.2019 को दूसरे कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया और 14.07.2019 को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए। याचिकाकर्ता ने 30.07.2019 को दूसरे कारण बताओ नोटिस के जवाब के समर्थन में एक याचिका भी दायर की है (अनुलग्नक-8 श्रृंखला), लेकिन उन सभी को नजरअंदाज करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने "बर्खास्तगी" की सजा दी है जो सामान्य रूप से भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी, जैसा कि पत्र संख्या 186 दिनांक 01.08.2019 और प्रशासनिक आदेश पत्र संख्या 187 दिनांक 01.08.2019 (अनुलग्नक-9 श्रृंखला) में निहित है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.09.2019 को अध्यक्ष-सह-अपीलीय प्राधिकारी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर के समक्ष अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया था (अनुलग्नक-10)

लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के आधार को समझे बिना ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2019 को याचिकाकर्ता को दी गई सजा (जैसा कि पत्र संख्या 322 दिनांक 23.10.2019 (अनुलग्नक-11) में निहित है) को यांत्रिक तरीके से बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के विचारार्थ विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं को उठाया कि प्रभार ज्ञापन के अनुसार 2006-07 और 2007-08 में ऋण स्वीकृत किए गए थे, उन्हें प्रशंसा पत्र जारी किया गया था और साथ ही वर्ष 2008-09 में स्केल-1 से स्केल-II में पदोन्नति भी दी गई थी। 2010 में, लेकिन जिस काम के लिए उनकी सराहना की गई और पदोन्नति दी गई, उसके लिए उन्हें अपने करियर के अंतिम समय में, विशेष रूप से उनकी सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही और दंड का सामना करना पड़ा है। वकील ने आगे कहा कि उक्त विभागीय कार्यवाही वर्ष 2006-08 में वितरित किए गए ऋणों के लिए वर्ष 2018 और 2019 में शुरू की गई थी, यानी ऋण स्वीकृत होने की तारीख से लगभग 11 साल बीत जाने के बाद। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय जांच की देरी से शुरुआत कर्मचारी जवाबदेही नीति के खंड 7 (xii) का घोर उल्लंघन है। इसके अनुसार किसी भी चूक के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, जिसका उल्लेख दो क्रमिक ऑडिट रिपोर्टों या घटना की तारीख से चार साल में नहीं किया गया है, जो भी बाद में हो। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विभागीय कार्यवाही की देरी से शुरूआत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पी.वी. महादेवन बनाम एम.डी.टी.एन. हाउसिंग बोर्ड** के मामले में निर्धारित अनुपात के मद्देनजर आरोप ज्ञापन को निष्प्रभावी बनाती है, जिसकी रिपोर्ट **2005(6) एस.सी.सी. 636** में दी गई थी।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि एल.आई.सी. पॉलिसियों के बारे में आरोप किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं हैं, क्योंकि उन्हें एल.आई.सी. की जारी करने वाली शाखा में सत्यापन के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि गलत नामों के साथ सत्यापन के लिए एक सारणीबद्ध चार्ट भेजा गया था, जिसके बारे में आरोप हैं कि वे पॉलिसियाँ फर्जी हैं, जिस पर जाँच अधिकारी द्वारा कोई निष्कर्ष/सत्यापन नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का बयान जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड से परे है और याचिकाकर्ता ने ऐसे बयान पर उसे जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देता है, जिसकी रिपोर्ट **2009(2) एससीसी 570** में दी गई है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह समझने में विफल रहे कि अधिकांश ऋण अचल संपत्ति के न्यायसंगत बंधक द्वारा सुरक्षित थे और कुछ ऋण खाते बंद कर दिए गए थे, जबकि केसीसी और सीसीजीईएन ऋण खातों को 1,00,000 रुपये तक किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने सुरक्षा के रूप में एलआईसी पॉलिसियां जमा करवाईं, जो दर्शाता है कि वह बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त विवेकशील थे। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण का बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति के न्यायसंगत बंधक द्वारा सुरक्षित था, तो बैंक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015-16 में ऋण खाता एनपीए हो जाने पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रतिवादी - बैंक ने चूककर्ता उधारकर्ता के खिलाफ प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'एस.ए.आर.एफ.ए.एस.आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के तहत कोई कार्यवाही शुरू किए बिना, इसके बजाय, बैंक ने ऋण की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र मामला दायर करने का विकल्प चुना है और बैंकिंग प्रणाली में जिम्मेदार व्यक्तियों ने 'एस.ए.आर.एफ.ए.एस.आई. अधिनियम के तहत वसूली के लिए सही कार्रवाई करने के लिए खुद को बचाने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बनाया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है। अपने करियर के अंतिम चरण में अपनी जान बचाने के लिए।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे दलील दी कि मान लीजिए कि याचिकाकर्ता ने कोई गलत काम किया है तो उस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि यह महज लापरवाही है, कदाचार नहीं। अपने समर्थन में उन्होंने **भारत संघ और अन्य बनाम जे. अहमद के रिपोर्ट 1979 (2) एस.सी.सी. 286 में दिए गए** फैसले का हवाला दिया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया कि किसी भी दृष्टिकोण से याचिकाकर्ता का मामला विभागीय कार्यवाही के दायरे में नहीं आता है, विशेषकर तब जब उसी कार्य के लिए उसकी सराहना की गई और उसे पदोन्नति दी गई और लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद, विशेष रूप से कर्मचारी जवाबदेही नीति के आलोक में, वह विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसके

परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, कम से कम इसे लापरवाही कहा जा सकता है।

11. दूसरी ओर बैंक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संबंधित समय में शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था। उसकी चूक और कमीशन के कृत्य के लिए 20.12.2018 को चार्ज मेमो जारी किया गया था। विभागीय कार्यवाही 25.01.2019 को शुरू करने का निर्णय लिया गया और यह 13.05.2019 को आयोजित की गई। जांच प्राधिकारी ने आरोपों को सिद्ध करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष 13.06.2019 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने बैंक के सेवा विनियमन 2010 के विनियमन 39 (1) (बी) (वी) के तहत याचिकाकर्ता को "बर्खास्तगी" के रूप में दंड दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की और अपीलीय प्राधिकारी ने 23.10.2019 को अंतिम आदेश पारित किया, जिसके द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई सजा को बरकरार रखा गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जांच में यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता शाखा प्रबंधक होने के नाते उधारकर्ता से लिए गए एलआईसी बांड को आवंटित करने में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय कार्यवाही में कोई प्रक्रियागत खामियां नहीं हैं। अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आदेश पारित किया है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता एक बैंक अधिकारी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना है। बैंक के वकील ने **बिनोद सिंह सुमित्रा बनाम इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक** के मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें **2018(3) पीएलजेआर 543** में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें एक प्रबंधक को प्रीक्रेडिट मूल्यांकन के बिना बड़ी संख्या में नकद और क्रेडिट ऋण स्वीकृत करने और जाली/फर्जी आईटी रिटर्न स्वीकार करने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

12. उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बीसी चतुर्वेदी बनाम भारत संघ** के मामले में **1995 (6) एससीसी 749** में दिए गए एक अन्य निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण अपीलीय प्राधिकरण के निष्कर्ष कुछ साक्ष्य पर आधारित हैं, न्यायालय/न्यायाधिकरण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता है और अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।

13. पक्षों की सुनवाई और दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चला कि याचिकाकर्ता ने 2006-08 की अवधि के दौरान कुछ ऋण स्वीकृत किए थे, जिन्हें बैंक द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। लगाए गए आरोप से यह पता चला कि चार्ज मेमो 20.12.2018 को जारी किया गया था, और याचिकाकर्ता 31.12.2018 को सेवानिवृत्त हो गया, यानी लगभग 11 वर्षों के अंतराल के बाद उसके खिलाफ यह कार्यवाही शुरू की गई है, जबकि स्टाफ जवाबदेही पुलिस के खंड 7 (xii) में निम्नलिखित कहा गया है:

> *"किसी भी चूक के लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, जिसे घटना की तारीख (यानी चूक की घटना) से 4 साल की अवधि में दो क्रमिक ऑडिट रिपोर्टों में इंगित नहीं किया गया है, जो भी बाद में हो। यदि पिछले निरीक्षण अवधि के कारण कोई बड़ी अनियमितता दूसरे अंकेक्षण/निरीक्षण के बाद पाई जाती है, तो संबंधित अंकेक्षक/निरीक्षक को जवाबदेह ठहराया जाएगा और कार्रवाई/अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यह समय सीमा (i) धोखाधड़ी (ii) अन्य आपराधिक अपराधों या (iii) ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी, जहां दुर्भावना का अनुमान लगाया जा सकता है।*

इस नीति में, एक राइडर बनाया गया है कि यह समय सीमा ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगी, (i) धोखाधड़ी (ii) अन्य आपराधिक अपराधों या (iii) जहां दुर्भावना का अनुमान लगाया जा सकता है।

14. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की उक्त नीति का अध्ययन करने के बाद इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नीति 12.03.2014 से लागू है और वर्ष 2018-19 में आरोप गठित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि आरोप तय किए जाने के समय उक्त स्टाफ जवाबदेही नीति अस्तित्व में आई और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और स्टाफ पर लागू थी। इस न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता का मामला सबसे खराब स्थिति में भी लापरवाही के दायरे में आता है और निश्चित रूप से न तो धोखाधड़ी है, न ही आपराधिक अपराध है और न ही दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के तहत है। इसलिए, इस आधार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की स्टाफ जवाबदेही नीति का खंड 7 (xii) स्वयं वर्तमान याचिकाकर्ता की रक्षा करता है।

15. इसके अलावा इस न्यायालय को यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता ने अपने बचाव के बयान, दूसरे कारण बताओ और साथ ही अपील के ज्ञापन और वर्तमान याचिका में लगातार अपनी दलीलों में यह स्पष्ट रूप से दलील दी है कि ऋण उधारकर्ता की अचल संपत्तियों को न्यायसंगत बंधक के तहत प्राप्त करने के बाद स्वीकृत किए गए थे और याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सुरक्षा प्रमुख के रूप में उधारकर्ता से एलआईसी बांड भी प्राप्त किए हैं। इसलिए, इस मामले के मद्देनजर, बैंक अधिकारी को उधारकर्ता के खिलाफ उनके खातों को एनपीए श्रेणी में घोषित करने के तुरंत बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों ने मामले को दबा दिया और बाद में अपनी खाल बचाने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को बलि का बकरा बना दिया, जो सेवानिवृत्त होने वाला था। इस पहलू पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय वर्तमान मामले को तय करने के उद्देश्य से **रूप सिंह नेगी (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित अनुपात का घोर उल्लंघन करता है, जिसके प्रासंगिक पैराग्राफ 14 और 15 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है: -

> *"**14.** निस्संदेह, विभागीय कार्यवाही एक अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है। जांच अधिकारी एक अर्ध-न्यायिक कार्य करता है। दोषी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाया जाना चाहिए। जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचे। जांच अधिकारी द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान एकत्र किए गए कथित साक्ष्य को अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य नहीं माना जा सकता। उक्त दस्तावेजों को साबित करने के लिए किसी गवाह की जांच नहीं की गई। प्रबंधन के गवाहों ने केवल दस्तावेज पेश किए और उनकी सामग्री को साबित नहीं किया। जांच अधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ एफआईआर पर भरोसा किया, जिसे सबूत नहीं माना जा सकता था।*
>
> ***15.** हमने पहले भी देखा है कि जांच अधिकारी द्वारा जिस एकमात्र बुनियादी साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह अपीलकर्ता द्वारा पुलिस के समक्ष किया गया कथित कबूलनामा है। अपीलकर्ता के अनुसार, उसे उक्त कबूलनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर*

किया गया था, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन में प्रताड़ित किया गया था। अपीलकर्ता बैंक का कर्मचारी है, इसलिए उक्त कबूलनामे को साबित किया जाना चाहिए था। यह दिखाने के लिए कुछ सबूत रिकॉर्ड पर लाए जाने चाहिए थे कि उसने बैंक ड्राफ्ट बुक चुराने में भाग लिया था। बेशक, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। यहां तक कि कोई अप्रत्यक्ष सबूत भी नहीं था। रिपोर्ट के सार से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने उसे दोषी मानने का मन बना लिया था, अन्यथा वह इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि अपराध इस तरह से किया गया था कि कोई सबूत नहीं बचा था।

इस आधार पर, यह इस न्यायालय को पता चलता है कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष गलत है।

16. **बिनोद कुमार सुमित्रा (सुप्रा)** के मामले में प्रतिवादी ने जिस निर्णय पर भरोसा किया, वह धोखाधड़ी और फर्जी आईटी रिटर्न स्वीकार करने से संबंधित है। वर्तमान मामले में, यह स्थिति नहीं है, बल्कि जांच रिपोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्पष्टीकरण पर विचार न करना इस न्यायालय के लिए प्रचलित है। इसी तरह **बी. सी. चतुर्वेदी (सुप्रा)** के मामले में दिए गए निर्णय में जो केवल तभी लागू होगा जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी का निष्कर्ष कुछ सबूतों पर आधारित हो, लेकिन वर्तमान मामले में अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष सबूतों पर आधारित नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अपने बचाव में लगातार की गई दलीलों और वर्तमान दलीलों का भी प्रतिवादी बैंक द्वारा विशेष रूप से जवाब नहीं दिया गया है।

17. ऊपर की गई चर्चाओं और बताए गए कारणों के मद्देनजर यह न्यायालय पत्र संख्या 383 दिनांक 20.12.2018 में निहित आरोप को खारिज करता है; जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2019 पत्र संख्या 135 दिनांक 29.05.2019 में निहित आदेश दिनांक 01.08.2019 पत्र संख्या 186 में निहित आदेश दिनांक 01.08.2019 पत्र संख्या 187 में निहित तथा आदेश दिनांक 23.10.2019 पत्र संख्या 322 दिनांक 23.10.2019 में निहित। प्रतिवादी बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को उसके सेवानिवृत्ति बकाया से संबंधित भुगतान इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह के भीतर करे।

18. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(डॉ. अंशुमान, न्यायमूर्ति)

अश्विनी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।